

ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया: संभावनाएं एवं चुनौतियां

¹डॉ० विकास मिश्रा

¹सहायक आचार्य, बी.एड. विभाग, अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, कानपुर देहात उ०प्र०

Abstract

ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कोई नया संप्रत्यय नहीं है परंतु कोरोना काल में यह अपरिहार्य एवं आवश्यक बन गया था। लॉकडाउन में सब कुछ थम गया था तथा जनसामान्य ने यह स्वीकार कर लिया था कि 'जान है तो जहान है'। जीवन का प्रत्येक पक्ष इससे प्रभावित हुआ था तथा शिक्षा व्यवस्था भी इससे अछूती न रह सकी। जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेबैक्स आदि डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने एक तरफ तो विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन मीटिंग के साथ जोड़े रखा तो वहीं 'कक्षा-कक्ष शिक्षण को भी संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे विद्यार्थियों का पठन-पाठन सुचारु रूप से संचालित हो सका।

बीज शब्द— शैक्षिक संसाधन, ऑनलाइन शिक्षण अधिगम, तकनीकी, संभावनाएं एवं चुनौतियां।

Introduction

शिक्षा में डिजिटल तकनीकी की उपादेयता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात् एनईपी 2020 में की गई निम्न अनुशंसाओं/ प्रावधानों के आधार पर हम इसको बखूबी समझ सकते हैं—

1. सकल नामांकन अनुपात अर्थात् जीईआर बढ़ाने के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार किया जाएगा।
2. शिक्षा का अंतर-राष्ट्रीयकरण किया जाएगा।
3. मेन्टरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी।
4. एबीसी अर्थात् एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा तथा शिक्षकों के प्रमोशन एवं अन्य विभागीय कार्यों हेतु इसका उपयोग किया जाएगा। विद्यार्थियों के किसी अन्य कोर्स में प्रवेश लेने पर क्रेडिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
5. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक-निर्धारक निकाय के रूप में परख (PARAKH) नामक एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
6. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा।

7. एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा।
8. डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।
9. स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपादित करने में सूचना संचार तकनीकी अर्थात् आईसीटी की अहम भूमिका है। सूचना संचार तकनीकी के उपयोग द्वारा हम शिक्षा प्रणाली में मौजूद अनेकों चुनौतियों से निपट सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षण में आईसीटी की भूमिका को निम्न विन्दुओं से समझा जा सकता है—
 1. यह शिक्षक क्षमता बढ़ाने और विद्यालय प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह पारंपरिक प्रशिक्षण और समर्थन विधियों की सीमित पहुंच की कमी से निपटने में मदद कर सकता है।
 2. आईसीटी का उपयोग पुस्तकों, चार्ट और अन्य प्रशिक्षण संसाधनों के डिजिटलीकरण के लिए किया जा सकता है जो विद्यालय प्रणाली में उपयोग किए जा रहे हैं। यह मुद्रण सामग्री को बचाने के साथ-साथ अध्ययन सामग्री की पहुंच को बढ़ाएगा।
 3. कंप्यूटर का उपयोग न केवल इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, अपितु इसका उपयोग शिक्षकों, छात्रों में विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और समस्या निवारण कौशल के निर्माण के लिए किया जा सकता है।
 4. एनईपी के दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
 5. प्रादेशिक भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री विकसित की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र में स्थापित शैक्षिक संस्थानों को अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
 6. विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
 7. डिजिटल तकनीक वर्तमान समय की मांग है अतः डिजिटल तकनीक को शिक्षा में शामिल करने और उसका क्रियान्वयन करने के लिए मानक नीति का निर्माण किया जाएगा।
 8. देश में तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा।

ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ने शिक्षा जगत में नवीन क्रांति को जन्म दिया है तथा शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है परंतु इसके साथ ही कुछ नई चुनौतियों को भी इसने जन्म दिया है, जो इस प्रकार हैं।

1. विद्यार्थी डिजिटल तकनीक का उपयोग शिक्षा में करने के बजाय मनोरंजन के साधन के रूप में अधिक कर रहे हैं तथा उनकी पहुंच अवांछित डिजिटल सामग्री तक हो गई है।
2. सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी की प्रमाणिकता संदेहास्पद है अतः विद्यार्थियों को प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है।
3. लगातार कंप्यूटर एवं मोबाइल के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ रहा है तथा डिजिटल एडिक्शन से विभिन्न मानसिक विकारों के शिकार हो रहे हैं।
4. कक्षा कक्ष में डिजिटल साधनों की नई तकनीकों के प्रयोग में अध्यापकों व विद्यार्थियों की कुशलता में कमी है।
5. तकनीकी में सीमाएं नहीं होती हैं यह एक अच्छी बात है परंतु यह एक चुनौती भी है कि संप्रेषण में सूचनाएं सही रूप में सही समय पर प्राप्त हों।
6. तकनीकी विधाएं महंगी होती हैं अतः सामान्य आर्थिक सामाजिक स्तर वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुलभ नहीं है।
7. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य भावनात्मक रूप से जुड़ाव होना महत्वपूर्ण माना गया है जोकि डिजिटल संसाधनों के माध्यम से संभव नहीं हो सकता है।
8. विज्ञान एवं तकनीकी ने एक और जहां हमारे जीवन को सुगम एवं सरल बनाया है वहीं कतिपय तकनीकी परेशानियां भी उत्पन्न की हैं। डिजिटल तकनीकी का उचित प्रयोग करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, डिजिटल इथिक्स को समझाने में शिक्षकों के साथ ही अभिभावकों को भी विशेष भूमिका निभानी होगी।
9. जब तक संपूर्ण समाज डिजिटल साक्षर नहीं होगा तब तक ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही मायनों में पूर्ण रूप से लागू करना एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।

उपरोक्त विन्दुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिभावक व अध्यापकों को विद्यार्थियों को तकनीकी के साथ सामंजस्य बनाने व उनके सुरक्षित व विश्वस्त सर्च करने के लिए प्रेरित करना उनकी डिजिटल जिम्मेदारी है। डिजिटल जिम्मेदारी में विषयवस्तु को कानूनी रूप से डाउनलोड करना, डिजिटल साधनों का सही प्रयोग करना, डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना आदि शामिल है। डिजिटल जिम्मेदारी विद्यार्थी एवं अध्यापक दोनों के लिए ही है। विद्यार्थी को अधिगम के समय विषयवस्तु पर केंद्रित होकर पढ़ने, अन्य मनोरंजक साइट से बचने, हैकर व अन्य ऑनलाइन जोखिम से बचने के साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अध्ययन की आवश्यकतानुसार सक्रिय रहने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अध्यापकों को सही विषयवस्तु प्रस्तुत करने, विद्यार्थियों को सही साइट्स

का प्रयोग करना सिखाने, डिजिटल अधिगम एवं शिक्षण को रुचिकर बनाने तथा विद्यार्थियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराने के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। यदि शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारियों का सही रूप से पालन करेंगे तो ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और भावी पीढ़ी उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने-अपने क्षेत्र में कुशल पेशेवर के रूप में राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेगी।

संदर्भ ग्रंथ—

1. भारत में गुणवत्ता पर उच्च शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षण (2021), डॉ. अरविंद कुमार शुक्ल, स्वरांजलि प्रकाशन, गाजियाबाद।
2. नई शिक्षा नीति 2020 वैश्विक एवं भारतीय संदर्भ में, स्मारिका— 2023, डॉ. राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज कानपुर।